

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग-2

संख्या-50 /XVIII(2)/2017/2(1)12/बागेश्वर/ 2016

देहरादून: दिनांक 31 जुलाई, 2017

विषय:-जनपद बागेश्वर के तहसील कपकोट के अन्तर्गत अत्यधिक संवेदनशील ग्राम दोबाड़, बड़ेत तथा सेरी के कुल 28 प्रभावित परिवारों के विस्थापन/पुनर्वास हेतु धनावंटन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-51/तेरह-06सी0आर0ए0/विस्थापन/2011-12 दिनांक 27 अप्रैल, 2017 एवं पत्र संख्या-201/तेरह-06सी0आर0ए0/विस्थापन/2011-12 दिनांक 17 जून, 2017 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बागेश्वर के तहसील कपकोट के अन्तर्गत अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में अवस्थित ग्राम दोबाड़ के 13 परिवार, एवं ग्राम-बड़ेत के 11 परिवार तथा ग्राम सेरी के 04 परिवार अर्थात् कुल 28 प्रभावित परिवारों के विस्थापन/पुनर्वास हेतु पुनर्वास नीति, 2011 के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिये भवन निर्माण हेतु रू0 3.00 लाख, गोशाला निर्माण हेतु रू0 15,000 तथा विस्थापन भत्ता के रूप में रू0 10,000 इस प्रकार कुल रू0 3.25 लाख प्रति परिवार की दर से 28 परिवारों हेतु कुल रू0 91 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा, जिस मद/प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी की होगी।
- 2- प्राकृतिक आपदा से संकटग्रस्त ग्रामों के अन्यत्र विस्थापन/पुनर्वास के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2063/XVIII-(2)/11-16(1)/2007 दिनांक 19 अगस्त, 2011 के माध्यम से जारी नीति/दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
- 3- ग्रामवासियों से इस बात का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि वे स्वयं प्रस्तावित भूमि पर बसने हेतु इच्छुक हैं एवं उन्हें प्रस्तावित भूमि में बसने में कोई आपत्ति नहीं है।
- 4- किसी परिवार के मुखिया के पुत्र/पुत्रियों को अलग-अलग परिवार तभी माना जायेगा, जबकि पुत्र-पुत्रियों का विवाह हो चुका हो एवं वे अलग-अलग निजी/स्वयं के मकानों में निवासरत हों। एक ही मकान में रह रहे परिवारों के सदस्यों को अलग-अलग लाभ नहीं दिया जायेगा।
- 5- स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति व मदवार व्यय विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- 6- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि विस्थापन हेतु चिन्हित ग्रामवासी की ग्रामसभा से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना नितांत आवश्यक होगा।

7- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-06 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-102 विनाश वाले क्षेत्रों में अकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध-04 दैवी आपादाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-83 मतदेय/वित्त अनु0-5/2017 दिनांक 27 जुलाई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या 50 (1)/XVIII(2)/2017/2(1)12/ बागेश्वर/ 2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी/मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. अपर सचिव, वित्त एवं व्यय उत्तराखण्ड शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
7. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
10. वित्त अनुभाग-5
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

31/07/17

(विनोद कुमार सुमन)
अपर सचिव।